नईदुनिया

संपादकीय

बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरता

बांग्लादेश में हसीना सरकार के पतन और उनके भारत में शरण लेने के बाद अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर जिस तरह लगातार हमले हो रहे हैं, इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी उसकी अगली कड़ी है। दास की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके वकील की निर्मम हत्या असहिष्णुता की पराकाष्ठा को ही दर्शाती है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि वहां अल्पसंख्यक किन भयावह स्थितियों का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे लोगों पर हमले तक किए गए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के पैरोकार दास को कथित रूप से बांग्लादेशी झंडे का अपमान करने तथा राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने के कारण बांग्लादेश और सीमा पार भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। दरअसल, इस अशांति का संदर्भ लगातार अल्पसंख्यक उत्पीड़न के पैटर्न में निहित हैं। बांग्लादेश के संवैधानिक आश्वासन के बावजूद वहां के हिंदू, जो कि आबादी का लगभग नौ फीसदी हैं, लगातार हिंसा, बर्बरता और सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। वहां हिंदुओं के घरों व मंदिरों पर भीड़ पर हमलों की खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। जिसमें हसीना सरकार के पतन के बाद खासी तेजी आई है। आधिकारिक रूप से इस्लामिक धर्म वाले इस देश में यह स्थिति अल्पसंख्यकों की व्यापक असुरक्षा को दर्शाती है। अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा सुरक्षा की गुहार लगाये जाने के बाद विश्वास बहाली की जिम्मेदारी कार्यवाहक सरकार पर है। जिसका दायित्व बनता है कि उत्पीड़न के शिकार लोगों को न्याय दिलाने के लिये विशेष न्यायाधिकरण के जरिये यथाशीघ्र कार्रवाई करे। यदि समय रहते ऐसा नहीं होता तो अशांति के बढ़ने का खतरा बना रहेगा। मौजूदा घटनाचक्र से बांग्लादेश की प्रगतिशील लोकतंत्र की छवि कमजोर हुई है। नि:संदेह, वहां सभी अल्पसंख्यकों के लिये शांति और सुरक्षा एक जीवंत वास्तविकता होनी चाहिए। ढाका सरकार को छात्र आंदोलन के जरिये हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद पनप रही कट्टरता पर अंकुश लगाना चाहिए।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लगातार उत्पीड़न के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं गाहे-बगाहे आती रही हैं। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर गंभीर चिंता जतायी थी। यहां तक कि ट्रांसपेरंसी इंटरनेशनल ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों पर बढ़े हमलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट में हसीना सरकार के पतन के बाद के एक पखवाड़े में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के दो हजार से अधिक मामलों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट इस बात पर भी चिंता जताती है कि ऐसे मामलों में अपराधियों की पहचान होने के बावजूद उन्हें दंडित नहीं किया गया। बल्कि इसके बहाने राजनीतिक विरोधियों को ही निशाना बनाया गया। ऐसी हिंसा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी तल्ख प्रतिक्रिया दर्ज की गई है। यह विडंबना ही है कि जिस बांग्लादेश की स्थापना भारत के त्याग व बलिदान के चलते एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हुई थी, आज वहां यूनस सरकार उन मूल्यों को ताक पर रख रही है। भारत सरकार के विरोध के बावजूद यूनस सरकार किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश का इतिहास बताता है कि जब-जब सेना के हाथ में सत्ता की बागडोर आई है, तो कट्टरपंथियों को संरक्षण मिला है। ऐसे में फौज द्वारा गठित अंतरिम सरकार से इस दिशा में किसी बड़ी पहल की उम्मीद करना बेमाने ही होगा। भारत सरकार को राजनीतिक व कूटनीतिक प्रयासों से अंतरिम सरकार पर दबाव बनाना होगा ताकि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दे। तभी कट्टरपंथियों की निरंतर जारी हिंसा पर अंकुश लगाने की उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ ही पाक समर्थित कट्टरपंथी संगठनों पर भी नियंत्रण करने के लिये दबाव बनाने की जरूरत है। वैसे अंतरिम सरकार के अड़ियल रवैये को देखते हुए बहुत ज्यादा उम्मीद इस दिशा में नजर नहीं आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव इस दिशा में एक उपाय हो सकता है।

इस बार खास होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव

दृष्टिकोण

-मनोज कुमार मिश्र

देश में होने वाला हर चुनाव खास ही होता है लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के करीब दो महीने बाद होने वाला दिल्ली विधानसभा का चुनाव ज्यादा ही खास होने वाला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे ने देश और खास कर दिल्ली का राजनीतिक समीकरण काफी बदल दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले भाजपा नंबर एक पार्टी बनी और लगातार तीसरी बार केन्द्र में भाजपा की अगुवाई में राजग सरकार बनी लेकिन भाजपा की सीटें कम होने से विपक्षी गठबंधन के हौसले बुलंद हुए। उसके बाद हुए जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में मान लिया गया था कि भाजपा को जीत नहीं मिलेगी। जम्मू एवं कश्मीर में भी भाजपा का प्रदर्शन बेहतर हुआ और हरियाणा में अप्रत्याशित ढंग से भाजपा सारे चुनावी विश्लेषकों के दावों की धज्जियां उड़ा कर पहले से ज्यादा सीटें लेकर सत्ता में आई। सत्ता की दावेदार मानी जा रही कांग्रेस को तो भारी सदमा लगा ही हरियाणा में चमत्कार करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी (आआपा) को भी भारी झटका लगा। आआपा के संयोजक और सर्वमान्य नेता अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कई नेताओं को शराब घोटाले के आरोप में जेल जाना पड़ा और वे काफी प्रयास करके सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर आ पाए। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली पार्टी के सामने अपने वजूद को बचाने की चुनौती है। यह चुनौती इसलिए भी बढ़ गई है कि हरियाणा के मूल निवासी केजरीवाल यहां अपनी पार्टी के किसी उम्मीदवार को जीत दिलाना तो दूर पार्टी को दो फीसदी वोट भी नहीं दिलवा पाए।

दिल्ली पर जिन राज्यों का सर्वाधिक प्रभाव है उसमें एक हरियाणा है। वहां भाजपा के तीसरी बार सरकार बनने के मायने गंभीर हैं। इससे दिल्ली में कांग्रेस की उपस्थिति की उम्मीद पर पानी फिरता दिख रहा है, आआपा को भी 2015 और 2020 के नतीजे दुहराने के लिए कठिन मेहनत करनी होगी। भाजपा दिल्ली की लोक सभा की सभी सीटें लगातार तीसरी बार जीत गई। भले केजरीवाल के मुकाबले उसके पास स्थानीय स्तर पर कोई दमदार नाम न हो लेकिन माहौल भाजपा के अभी खिलाफ भी नहीं लग रहा है। लगातार दो बार दिल्ली विधान सभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाली आआपा ने दिल्ली के बाद पंजाब और दिल्ली नगर निगम चुनाव जीतने के बाद न केवल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाया बल्कि अपने को भाजपा के वैकल्पिक दलों में शामिल करवा लिया। पिछले तीन सालों में आआपा के कट्टर ईमानदार होने के दावे को शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोपों से भारी नुकसान पहुंचा है। केजरीवाल समेत आआपा के सभी नेता केन्द्र की भाजपा सरकार पर केन्द्रीय जांच एजेंसियों से प्रताड़ित कराने का आरोप लगाते रहे हैं। इसे उन्होंने लोक सभा से लेकर हरियाणा विधान सभा चुनाव में मुद्दा बनाया। इसका लाभ उन्हें दोनों चुनावों में नहीं मिला। जेल से बाहर आकर केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ कर अपने सहयोगी आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। वे फिर से दिल्ली जीतने की रणनीति में जुट गए हैं।

हरियाणा के चुनाव से पहले जो वातावरण बना था, उसे हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों ने बदल दिया। इस मई में हुए लोक सभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम आई। भले उसकी केन्द्र में सरकार बन गई लेकिन भाजपा नेताओं के हौसले पस्त दिखने लगे थे। उसी तरह दिल्ली में कोई सीट न जीतने के बावजूद कांग्रेस और आआपा के हौसले बढ़ गए थे। चुनाव पूर्वानुमानों के उत्साह में कांग्रेस और आआपा अकेले चुनाव लड़े। कांग्रेस को तो भाजपा के 48 के मुकाबले 37 सीटें मिल गई लेकिन आआपा को दो फीसदी से भी कम उसे वोट मिले। दिल्ली का राजनीतिक समीकरण लगातार बदलता रहा है। 1483 वर्ग किलोमीटर की दिल्ली आजादी से पहले तीन सौ से ज्यादा गांवों और मुगल बादशाह शाहजहां के बसाए शाहजहांनाबाद (पुरानी दिल्ली) के लोगों की थी। देश के विभाजन के बाद बड़ी तादाद में पाकिस्तान से हिंदू और सिख शरणार्थी आए। देश की राजधानी होने के चलते बड़ी तादाद में केन्द्र सरकार के कर्मचारी देशभर से आए। उसी तरह बेहतर शिक्षा के लिए देश के पिछड़े राज्यों से विद्यार्थी आए। उत्तराखंड और पड़ोस के राज्यों से पलायान भी तभी शुरू हो गया था लेकिन बड़े पैमाने पर पलायन 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों के लिए हुए निर्माण कार्यों में मजदूरों की जरूरत से हुआ।

कुछ सालों तक बाहर से आने वाले केवल दिल्ली में काम के लिए आते थे और उनका स्थायी निवास अपने मूल स्थान पर होता था। वे वहीं के मतदाता थे। दूसरी पीढ़ी आने के बाद वे दिल्ली और आसपास के इलाकों (एनसीआर) के मतदाता बने और तीसरी पीढ़ी आने के बाद तो वे सत्ता को प्रभावित करने लगे। पहले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि प्रदेशों के मूल निवासी दिल्ली में चुनाव लड़ने और जीतने लगे और फिर वह दौर आ गया जब बिहार मूल के महाबल मिश्र और मनोज तिवारी दिल्ली के सांसद बन गए। मनोज तिवारी को तो एक खास वर्ग की पार्टी कही जाने वाली भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यह संख्या और अनुपात लगातार बढ़ता जा रहा है। जो हाल अभी दिल्ली का दिख रहा है यही हरियाणा और पंजाब का भी हो गया है। इसे राजनीतिक कारणों से भले अभी नहीं स्वीकारा जा रहा है लेकिन अगले कुछ सालों में इसे सभी स्वीकारेंगे। अभी हरियाणा विधान सभा चुनाव में कांग्रेस एक जाति विशेष का दबदबा मान कर उसी को साथ लेने में लगी रही और बाकी जातियों ने प्रतिक्रिया में भाजपा को जिता दिया।

दिल्ली में भी आआपा के ताकतवर होने का एक कारण तो फ्री बिजली-पानी देना है लेकिन दूसरा बड़ा कारण खुले मन से प्रवासियों को साथ लाना है। यह काम पहले कांग्रेस करती थी। उसे लगातार दिल्ली में जीत मिलने के बाद लगा कि अब तो प्रवासी उनके स्थाई मतदाता बन गए। उन्होंने उनको महत्व देना कम किया तो उनकी जगह आआपा ने ले लिया। दिल्ली का हर पांचवां मतदाता पूर्वांचल (बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर मूल) का प्रवासी है। उनके समर्थन के बिना दिल्ली नहीं जीती जा सकती। राजनीति के खेल में कई रिकार्ड बनाने वाले आआपा संयोजक और अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बन गए अरविंद केजरीवाल के सामने अपनी और अपनी पार्टी की साख (यूएसपी) बचाने का संकट है। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले केजरीवाल और उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार का केवल आरोप नहीं लगा है बल्कि शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल समेत अनेक बड़े नेता जेल भी गए।

भारतीय आर्थिक दर्शन एवं प्राचीन भारत में आर्थिक विकास

नजरिया

- प्रहलाद सबनानी

प्राचीन भारत के वेद-पुराणों में धन अर्जित करने को बुरा नहीं माना गया है। प्राचीन काल में वेदों का एक भाष्यकार हुआ, जिसका नाम यासक था। यासक ने 'निघंटू' नामक ग्रंथ में धन के 28 समानार्थ शब्द बताए हैं और प्रत्येक शब्द का अलग-अलग अर्थ है। दुनिया की किसी पुस्तक अथवा किसी अर्थशास्त्र की किताब में धन के 28 समानार्थ शब्द नहीं मिलते हैं। भारत के शास्त्रों में धन के सम्बंध में उच्च विचार बताए गए हैं।

भारत में वेदों, पुराणों एवं शास्त्रों में यह कहा गया है कि मानव जीवन हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अच्छे कर्मों का करना आवश्यक है। अच्छे कर्म अर्थात हमारे किसी कार्य से किसी पशु-पक्षी, जीव-जंतु को कोई दु:ख नहीं पहुंचे एवं सर्व समाज की भलाई के कार्य करते रहें। अर्थात, इस धरा पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो, मंगल हो। ऐसी कामना भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में की जाती है।

इसी प्रकार, धर्म के महत्व को स्वीकार करते हुए कौटिल्य के अर्थशास्त्र, नारद की नारद स्मृति और याग्वल्य की याग्वल्य स्मृति में कहा गया है कि 'अर्थशास्त्रास्तु बलवत धर्मशास्त्र नीतिस्थिति'। अर्थात, यदि अर्थशास्त्र के सिद्धांत एवं नैतिकता के सिद्धांत के बीच कभी विवाद उत्पन्न हो जाए तो दोनों में से किसे चुनना चाहिए। कौटिल्य, नारद एवं याग्वल्य कहते हैं कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की तुलना में यानी केवल पैसा कमाने के सिद्धांतों की तुलना में हमको धर्मशास्त्र के सिद्धांत अर्थात नैतिकता, संयम, जिससे समाज का भला होता हो, उसको चुनना चाहिए। कुल मिलाकर अर्थतंत्र धर्म के आधार पर चलना चाहिए। गुनार मृडल जिनको नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था एवं जिनकी 'एशियन ड्रामा' नामक पुस्तक बहुत मशहूर हुई थी। उन्होंने एक और छोटी किताब लिखी है जिसका नाम है 'अगेन्स्ट द स्ट्रीम'। इस किताब में उन्होंने अर्थशास्त्र को एक नैतिक विज्ञान बताया है। कुछ वर्ष पूर्व अखबारों में एक खबर छपी थी कि विश्व बैंक ने यह जानने के लिए एक अधय्यन प्रारम्भ किया है कि विकास में आध्यात्म की कितनी भूमिका है। इसी प्रकार दुनिया में यह जानने का प्रयास भी किया जा रहा है कि दरिद्रता मिटाने में धर्म की क्या भूमिका हो सकती है।

प्राचीन भारत के वेद-पुराणों में धन अर्जित करने को बुरा नहीं माना गया है। प्राचीन काल में वेदों का एक भाष्यकार हुआ, जिसका नाम यासक था। यासक ने 'निघंटू' नामक ग्रंथ में धन के 28 समानार्थ शब्द बताए हैं और प्रत्येक शब्द का अलग-अलग अर्थ है। दुनिया की किसी पुस्तक अथवा किसी अर्थशास्त्र की किताब में धन के 28 समानार्थ शब्द नहीं मिलते हैं। भारत के शास्त्रों में धन के सम्बंध में उच्च विचार बताए गए हैं। भारत के शास्त्रों ने अर्थ के क्षेत्र को हेय दृष्टि से नहीं देखा है एवं यह भी कभी नहीं कहा है कि धन अर्जन नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए, उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहिए। बल्कि दरिद्रता एवं गरीबी को पाप बताया गया है। हां, वेदों में यह जरूर कहा गया है कि जो भी धन कमाओ वह शुद्ध होना चाहिए। 'ब्लैक मनी' नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार करके धन नहीं कमाना चाहिए, स्मगलिंग करके धन नहीं कमाना चाहिए, कानून का उल्लंघन करते हुए धन अर्जन नहीं करना चाहिए, ग्राहक को धोखा देकर धन नहीं कमाना चाहिए। मनु स्मृति में तो मनु महाराज ने कहा है कि सब प्रकार की शुद्धियों में सर्वाधिक महत्व की शुद्धि अर्थ की शुद्धि है। भारतीय शास्त्रों में खूब धन अर्जन करने के बाद इसके उपयोग के सम्बंध में व्याख्या की गई है। अर्जित किए धन को केवल अपने लिए उपभोग करना, उस धन से केवल ऐय्याशी करना, केवल अपने लिए काम में लेना, अपने परिवार के लिए मौज-मस्ती करना आदि को ठीक नहीं माना गया है। अर्जित किए गए धन को समाज के साथ मिल बांटकर, समाज के हितार्थ उपयोग करना चाहिए। भारत के प्राचीन ग्रंथों में जीवन के उद्देश्य को पुरुषार्थ से जोड़ते हुआ यह कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन चारों बातों पर विचार करके मनुष्य को सुखी करने के सम्बंध में विचार किया जाना चाहिए। इसी विचार के चलते भारत के मनीषियों द्वारा अर्थ और काम को नकारा नहीं गया है। कई बार भारत के बारे में वैश्विक स्तर पर इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जाता रहा है कि भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में तो अर्थ और काम को नकार दिया गया है। प्राचीन काल में भी ऐसा कतई नहीं हुआ है। अगर, ऐसा हुआ होता तो भारत सोने की चिड़िया कैसे बनता? हां, भारत के प्राचीन शास्त्रों में यह जरूर कहा गया है कि अर्थ और काम को बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थ और काम को मर्यादा में ही रहना चाहिए। धन अर्जित करने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है परंतु यह धर्म का पालन करते हुए कमाना चाहिए। अर्थात, अर्थ को धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार काम को भी धर्म के साथ जोड़ा गया है। उपभोग यदि धर्म सम्मत और मर्यादित होगा तो इस धरा का दोहन भी सीमा के अंदर ही रहेगा। अत: कुल मिलाकर अर्थशास्त्र में भी नैतिकता का पालन होना चाहिए।

प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र एवं वर्तमान अर्थशास्त्र में यह भी एक बहुत बड़ा अंतर है। आजकल कहा जाता है कि नीति का अर्थशास्त्र से कोई लेना-देना नहीं है। जबकि वस्तुत: ऐसी कोई भी अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र और विकास का कोई भी तंत्र जिसमें नैतिकता को स्वीकार न किया जाय वह चल नहीं सकती और वह समाज का भला नहीं कर सकती। अर्थ को प्रदान किए गए महत्व के चलते ही प्राचीनकाल में भारत में दूध की नदियां बहती थीं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत का आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व में बोलबाला था।

आजकल

जलवायु संकट ने दी दस्तक

जलवायु संकट के प्रतिकूल नतीजे दुनिया भर में दिखने लगे हैं। कहीं समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो कहीं फसलें सूखे की मार झेल रही हैं। हिमनदों के पिघलने और चक्रवाती हवाओं से मनुष्यों के सामने अस्तित्व का संकट गहराने लगा है। दुनियाभर में और खासकर भारत में जिस तरह मौसम का मिजाज बिगड़ा है, यह जलवायु संकट के गंभीर होने का संकेत है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय में हिमालयी क्षेत्र में हिमनदों और झीलों का क्षेत्रफल बढ़ना खतरे की घंटी है। क्या हम फिर केदारनाथ जैसी किसी त्रासदी की प्रतीक्षा कर रहे हैं भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा पहले से ही है।

लिहाजा हिमनदों और झीलों के विस्तार को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि इससे न केवल ब्रह्मपुत्र और गंगा जैसी नदियों में पानी की मात्रा पर असर पड़ेगा, बल्कि जैव विविधता के साथ जन-जीवन भी व्यापक रूप से प्रभावित होगा। केंद्रीय जल आयोग की रपट को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय हरित पंचाट का केंद्र सरकार को नोटिस सजग करने के लिए ही है। इससे समय रहते हिमनदों को संभालने और नदियों के प्रबंधन की दिशा में कार्य शुरू होगा। हालांकि इसके लिए अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

केंद्रीय जल आयोग की रपट ने संभावित प्राकृतिक आपदा की तस्वीर सामने रखी है और इससे आंखें मूंदे नहीं रहा जा सकता। हिमनदों और झीलों के फटने से बाढ़ का अंदेशा तो है ही, और अगर ऐसा हुआ तो निचले इलाके में रहने वाले लाखों लोगों और जैव-विविधता के लिए यह भयावह होगा। भारत में जिन 67 झीलों की पहचान हुई है, उनके क्षेत्रफल में 40 फीसद की वृद्धि चिंता का विषय है। क्योंकि हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे राज्यों में यह विस्तार जोखिम बढ़ा सकता है। इन सभी परिस्थितियों के लिए कहीं न कहीं हम सभी दोषी हैं। हिमनदों का पिघलना कोई एक दिन में नहीं हुआ। कार्बन उत्सर्जन को रोक पाने में नाकामी तो है ही, वहीं जलवायु संकट पर उपेक्षा का भाव भी कम जिम्मेदार नहीं। ऐसे में पूर्व चेतावनी प्रणाली बनाने के साथ आपदा प्रबंधन पर ठोस कार्य करने की भी जरूरत है।

समय रहते जांच और उपचार से जीवन रक्षा

ज्ञानेन्द्र रावत

फ्लोरोसिस एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण पानी में फ्लोराइड की अधिकता है, जिसके चलते हड्डियां, दांत, किडनी और अन्य शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस रोग से प्रभावित लोग, विशेष रूप से गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में हैं, जहां पानी की खपत अधिक होती है। भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, जहां लोग हैंडपंप या कुओं का पानी उपयोग करते हैं।

फ्लोरोसिस के कारण लोगों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जिससे रीढ़ और शरीर के अन्य हिस्सों की हड्डियां टेढ़ी-मेढ़ी हो गई हैं। बच्चों के दांतों में पीलापन, छेद या टूटने की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा, हड्डियों में सूजन, जोड़ों में दर्द, घुटनों में सूजन और झुकने या बैठने में कठिनाई जैसे लक्षण भी देखे जा रहे हैं।

इसके साथ ही पेट भारी रहना, कब्ज, प्यास न बुझना और किडनी के रोग भी बढ़ रहे हैं। अक्सर लोग हड्डियों के दर्द को गठिया समझ लेते हैं, लेकिन ये फ्लोरोसिस के लक्षण हो सकते हैं।

फ्लोरोसिस मुख्य रूप से दांतों को प्रभावित करने वाली एक कास्मेटिक स्थिति है, जो जीवन के पहले आठ वर्षों में फ्लोराइड के अधिक सेवन के कारण होती है, जब दांत बन रहे होते हैं। भारत के कई राज्य भूजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से प्रभावित हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु प्रमुख हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, पानी के अलावा गेहूं, चावल और आलू जैसे खाद्य पदार्थों से भी फ्लोरोसिस हो सकता है। दिल्ली के कुछ इलाकों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में भी फ्लोराइड की अधिक मात्रा से लोग प्रभावित हैं।

फ्लोरोसिस के बारे में जागरूकता का अभाव इसके बढ़ने का मुख्य कारण है। जल प्रदूषण, भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ने इस बीमारी को फैलने का मौका दिया है। शोध से पुष्टि हुई है कि फ्लोरोसिस किसी भी उम्र में हो सकता है, और यदि समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह गंभीर हो सकता है। बच्चों में डेंटल फ्लोरोसिस अधिक होता है, जिसके कारण उनके दांत कमजोर, पीलापन, छेद, धब्बे और गैप की समस्या उत्पन्न होती है। फ्लोरोसिस शरीर में पोटेशियम की वृद्धि और कैल्शियम की कमी का कारण बनता है।

विशेषज्ञों के अनुसार फ्लोरोसिस होने के बाद किसी भी व्यक्ति का सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि फ्लोरोसिस होने ही नहीं दिया जाए। यह ध्यान देने वाली बात है कि यह केवल दूषित पानी से ही नहीं होता, पानी के अलावा भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

बीते दिनों नयी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में क्लिनिकल ईकोटैक्सियोलॉजी फेसिलिटी की ओर से तीन दिवसीय 36वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल सोसायटी फॉर फ्लोरोसिस रिसर्च का आयोजन हुआ। इसमें भारत के अलावा जापान, थाईलैंड, चीन, ईरान और अन्य देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए, जिन्होंने भूजल स्तर नीचे खिसकने समेत बहुतेरे कारणों की वजह से पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने के चलते फ्लोरोसिस की व्यापकता और बीमारी से निपटने के उपायों पर गहनता से विचार-विमर्श किया।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजधानी क्षेत्र में भी फ्लोराइड की निर्धारित मात्रा मानक से कहीं बहुत ज्यादा है। यहां रहने वाले फ्लोराइड जनित बीमारियों से परेशान हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से न तो रंग में कोई बदलाव आता है और न ही स्वाद में कोई अंतर ही आता है। ऐसी स्थिति में इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। उनके अनुसार ज्यादातर जलस्रोतों में प्राकृतिक रूप से भी फ्लोराइड पाया जाता है। यह भूजल में चट्टानों के कटाव से भी आता है। यही नहीं, आग या विस्फोट से पानी अत्यधिक गंदा होने से भी पानी में फ्लोराइड बढ़ रहा है।

चिकित्सकों का कहना है कि बचाव ही फ्लोरोसिस का सबसे बेहतर इलाज है। पानी में ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड है तो उसमें फिल्टर लगाया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में प्राथमिक स्तर पर बीमारी का पता चल जाता है तो एक्सरसाइज या दूसरे तरीकों से आसानी से उसका इलाज किया जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन-सी युक्त भोजन के अभाव में भी फ्लोरोसिस की आशंका बढ़ जाती है। इससे बचाव हेतु एंटीऑक्सीडेंट्स आदि की प्रचुरता वाला भोजन लें।

विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्टर करके पानी उपयोग करें। बारिश का पानी जमा करके इस्तेमाल में लाएं । खून की जांच कराएं, जिससे फ्लोराइड की मौजूदगी का पता चल जाता है। यदि पानी में फ्लोराइड की मात्रा 0.05 एमजी/लीटर है, तो यह सेहत के लिए खतरनाक है। एक्सरे की मदद से स्केलेटल फ्लोरोसिस का पता लग जाता है।

हमें खासकर हड्डियों का भी एक्सरे कराना चाहिए, जिससे बीमारी का पता लग जाता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि जागरूक रहना फ्लोरोसिस को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है।